क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 51, शुक्रवार, 15 मार्च, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

लोकसभा चुनावः एनसीपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सुप्रिया सुले को बारामती से मिला टिकट

नेशनल डेस्क। लोकसभा चुनाव को लेकर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि, एनसीपी-कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए सीटों का औपचारिक बंटवारा घोषित नहीं किया है। लेकिन माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस के पास 26 सीटें तो एनसीपी के पास 22 सीटें रहेंगे। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट हैं। बारामती से सुप्रिया सुले को उम्मीदवार बनाया गया है। कोल्हापुर से धनंजय महाडिक, ठाणे से आनंद परांजपे, रायगढ़ से सुनील तत्कारे, कल्याण से बाबाजी पाटिल, मुंबई उत्तर पूर्व से संजय दीना पाटिल, लक्षद्वीप से मोहम्मद फैसल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं एक सीट स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के लिए छोड़ी गई है, जो हातकणंगले से उम्मीदवार उतारेगा। दूसरी सूची शुक्रवार को आ सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 41 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की थी तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को केवल 6 सीटें मिली थीं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव चारण चरणों में होगें। 11, 18, 23 और 29 अप्रैल। पहले चरण यानी 11 अप्रैल को विदर्भ क्षेत्र में मतदान होगा, जबकि मुंबई की सभी सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा।

शीला दीक्षित का बड़ा बयान, आतंकवाद के खिलाफ मनमोहन सिंह ने नहीं उठाए कड़े कदम

नेशनल डेस्क। दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका यह बयान आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। गुरुवार को क इंटरव्यू में शीला दीक्षित ने स्वीकार किया कि मनमोहन सिंह आतंकवाद से लड़ने में उतने कठोर नहीं थे, जितने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि इसके साथ ही शीला ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी के ज्यादातर काम राजनीति से प्ररित होते हैं और राजनीतिक फायदे के लिए होते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद शीला दीक्षित ने सफाई दी है कि मनमोहन सिंह का आतंकवाद को लेकर उतना कड़ा कदम नहीं होता था, जितना कि पीएम मोदी उठाते हं। अगर मेरे बयान को किसी दूसरी तरह पेश किया जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। गौरतलब है कि शीला दीक्षित ने लगातार तीन बार दिल्ली की कमान संभाली है और वर्तमान में वह दिल्ली कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। इससे पहले वह केरल की राज्यपाल भी रह चुकीं हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया गया था। हालांकि अखिलेश यादव से गठबंधन के बाद शीला दीक्षित की दावेदारी खत्म हो गई।

छत्तीसगढ़ः

कांग्रेस के गढ़ में जीत का चौका मारने को तैयार भाजपा

नेशनल डेस्क।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का गढ़ रहे जांजगीर-चांपा लोकसभा सीट पर जीत की हैट्रिक बना चुकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब यहां चौका मारने के प्रयास में है। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक कलचुरी राजवंश के महाराजा जांज्वल्य देव ने इस क्षेत्र को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका जांजगीर नाम पड़ा। कोसा, कांसा और कंचन के उत्पादन एवं व्यापार को लेकर विख्यात और हिन्दू पुराण के मुताबिक भगवान राम के वनवास काल में शिवरीनारायण आगमन के दौरान शबरी द्वारा उन्हें जूठे बेर खिलाये जाने संबंधी कई प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर प्रसिद्ध जांजगीर-चांपा क्षेत्र वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव के दौरान संसदीय क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में नहीं था। अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे जांजगीर (अब छत्तीसगढ़) का 1957 के चुनाव के दौरान संसदीय क्षेत्र के रूप में गठन किया गया। उस चुनाव में कांग्रेस के सरदार अमर सिंह सहगल और मिनी माता अगम (बलौदाबाजार) निर्वाचित हुए। वर्ष 1962 के चुनाव में भी सहगल और मिनी माता (बलौदाबाजार) से निर्वाचित हुई। वर्ष 1967 और उसके बाद 1971 के आम चुनाव में जांजगीर(सु) लोकसभा सीट से मिनी माता ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लगातार जीत हासिल की। वर्ष 1973 में मिनी माता की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु के उपरांत रिक्त जांजगीर सीट के लिए 1974 में हुये उपचुनाव में कांग्रेस के ही भगतराम मनहर विजयी हुए। आपातकाल के बाद 1977 में हुए आम चुनाव के दौरान जांजगीर लोकसभा सीट सामान्य श्रेणी में आरक्षित कर दी गयी। आपातकाल के विरोध में उठे देशव्यापी लहर का असर यहां भी पड़ा और कांग्रेस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार के चुनाव में जनता पार्टी के मदनलाल शुक्ला ने जीत हासिल की। इसके बाद जितने भी आम चुनाव हुए उनमें कांग्रेस और भाजपा के बीच शह और मात का खेल चलता रहा। वर्ष 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस के रामगोपाल तिवारी ने चुनाव जीता। 'धान का कटोरा' माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में जांजगीर-चांपा धान का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जांजगीर-चांपा संसदीय क्षेत्र की कुल आबादी में एक तिहाई हिस्सा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की है और यह वर्ग किसी भी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक के रूप में काफी अहमियत रखता है। अस्सी के दशक में कांशीराम का ध्यान इस अनुसूचित जाति बहुल इलाके पर गया। इस वर्ग के उत्थान के उद्देश्य को लेकर बहुजन समाज पार्टी का गठन करने से पूर्व उन्होंने पहले डी-एस फोर और उसके बाद बामसेफ संगठन को आकार दिया था। कांशीराम ने अनुसूचित जाति के वोट बैंक का लाभ उठाने के लिए 1984 में अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव इस सीट पर लड़ा। किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रभात कुमार मिश्र ने यह चुनाव जीता। वर्ष 1989 में जांजगीर लोकसभा सीट पर भाजपा ने जशपुर क्षेत्र के लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह जूदेव पर दांव खेला और यह सफल भी रहा, लेकिन 1991 में कांग्रेस के भवानीलाल वर्मा ने भाजपा से यह सीट छीन ली। वर्ष 1996 में भाजपा के मनहरण लाल पांडेय विजयी हुए। इसके बाद 1998 में कांग्रेस ने यह सीट पुन- हथियाई और 1999 में भी अपना कब्जा बरकरार रखा। दोनों चुनाव में कांग्रेस के चरणदास महंत निर्वाचित हुए। एक नवम्बर 2000 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2004 में आम चुनाव हुए। तब इस सीट का नाम जांजगीर-चांपा हो गया। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा शुक्ला को अपना उम्मीदवार बनाया और इस पर एक बार फिर अपना कब्जा किया। बदली परिस्थिति में शुक्ला अब कांग्रेस में है। इसके बाद 2009 और 2014 में यहां से लगातार दो आम चुनाव जीतकर भाजपा ने हैट्रिक बनायी।

इन दोनों चुनावों में भाजपा की श्रीमती कमला पाटले ने जीत का परचम लहराया है। पाटले ने बताया कि इस बार भी उन्हें भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने का विश्वास जताया और अपनी जीत की हैट्रिक बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में निस्संदेह भाजपा की जीत तय है।

उन्होंने जोर दिया कि जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर पूरा भरोसा है और वह भली-भांति जानती और समझती है कि देश का भविष्य किनके हाथों में सुरक्षित है। कोसा (टसर सिल्क) के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में बनी कोसे की साड़ियों और अन्य कपड़ों की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि यहां आने वाले देश-विदेश की जानी-मानी हस्तियों तथा स्थानीय मेहमानों को भी उपहारस्वरूप कोसे की साड़ियां अथवा वस्त्र भेंट किए जाते हैं।

अजहर पर चीन का अड़ंगा, कूटनीतिक विफलताः सुरजेवाला

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सुरक्षा परिषद् में मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में चीन के अड़ंगे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई के लिए बड़ा झटका है और इससे साफ हो गया है कि चीन पाकिस्तान में आतंकवाद के साथ खड़ा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने गुरुवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करा पाना कूटनीतिक विफलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति ढुलमुल तथा बहुत कमजोर रही है और इसी का परिणाम है कि जैश सरगना को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने में चीन ने फिर अडंगा लगा दिया। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के समर्थन के बावजूद चीन के वीटो के कारण मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं करा पाने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चीन को शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर 'उपहार' स्थान दिलाने संबंधी आरोप पर सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा जब भी अपनी नीतियों के कारण विफल होती है तो उसे पंडित नेहरू याद आ जाते हैं। अपनी विफलता को वह पंडित नेहरू के आवरण में छिपाने का प्रयास शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन 1945 में हुआ था और तब तक भारत आजाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद अब तक इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन ने डोकलाम में सैन्य कॉम्पलेक्स बना दिया।

करतारपुर कॉरिडोरः

सकारात्मक रही भारत-पाक वार्ता, कई मुद्दों पर बनी सहमति

इस्लामाबाद।

पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में बढ़ी तल्खी कम करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर के मसौदा समझौते पर चर्चा के लिए पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आज 14 मार्च को भारत आया। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर आवश्यक विचार-विमर्श करने व महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए अटारी-वाघा बॉर्डर पर आज भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधियों का संयुक्त बयान सामने आया। इसमें बताया गया कि बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों देशों के बीच बैठक हुई। इस बैठक में करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं व दर्शन करने के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान सरकार और भारत सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया गया। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है और कुछ पर विचार किया जाना है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों देशों की तरफ से कॉरिडोर के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से भी बातचीत की गई। मुद्दे को लेकर अब अगली बैठक 2 अप्रैल 2019 को होगी।

इस बीच दोनों देशों की सरकारों से बातचीत करके प्रस्ताव में शामिल किए गए प्रावधानों पर बात की जाएगी। इसके बाद भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी 28 मार्च को इस्लामाबाद का दौरा करेगा। इस बैठक को दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच तनाव घटाने में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा कि जब तक पाक आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब तक उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है।उन्होंने कहा कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते हैं।

सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इतने ही उदार हैं तो मसूद अजहर को भारत को क्यों नहीं सौंप देते। उधर, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने इसकी पुष्टि की है और इस फैसले की जानकारी देने के लिए भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त गौरव अहलुवालिया को विदेश मंत्रालय बुलाया।

शिवसेना की भाजपा को सलाह- विपक्षी दलों के नेताओं को शामिल करते समय रहें सावधान

मुंबई। शिवसेना ने अपने सहयोगी दल भाजपा को विपक्षी दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते समय सावधानी बरतने की बृहस्पतिवार को सलाह दी और कहा कि ऐसा करने से भविष्य में समस्या पैदा हो सकती है। यह बयान महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटील के बेटे को भाजपा में शामिल किए जाने के बाद आया है। शिवसेना ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ब्लॉग पोस्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार ''पर्यायवाची'' हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में एक संपादकीय में कहा, ''कांग्रेस और राकांपा से नेताओं का आना आज लाभकारी लग सकता है लेकिन इससे भविष्य में समस्या पैदा हो सकती है, हमारा अनुभव यही कहता है। लोग आज आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता है। जब कुछ नहीं होगा, वे अन्य लोगों से संबंध जोड़ेंगे।'' उसने कहा कि राधाकृष्ण विखे पाटील शिव सेना के सदस्य थे और शिवसेना ने उन्हें एवं उनके पिता को क्रमशः राज्य एवं केंद्र सरकारों में मंत्री बनाया। उसने कहा, ''लेकिन सरकार के सत्ता से बाहर जाने पर वह हमारे खिलाफ हो गए। विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने विपक्षी नेता की तरह व्यवहार नहीं किया। सत्ता में रहने के दौरान भी उन्होंने शिवसेना की तरह (कई मामलों पर) मजबूत रुख नहीं अपनाया। इसके विपरीत उन्होंने हमारा विरोध किया।'' पार्टी ने कहा कि अब हालात ऐसे हैं कि लोग उनसे नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं।

जमीन घोटालों में वाड्रा के साथ मजबूती से खड़े हैं राहुल गांधीःभाजपा

नेशनल डेस्क।

भाजपा ने लगातार दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पर जमीन सौदे से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा किया कि राबर्ट वाड्रा से संबंधित सभी जमीन घपलों में राहुल गांधी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार से जुड़ी जमीन की खरीद फरोख्त का मामला उठाया था। उस पर कांग्रेस ने कहा है कि राहुल गांधी ने जमीन खरीदी और अपनी बहन को भेंट कर दी। प्रसाद ने कहा कि मामला जमीन खरीदने का नहीं बल्कि जमीन किससे खरीदी गई, ये मुख्य विषय है। जमीन एक ही व्यक्ति से खरीदी गई, यह भी मुख्य विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार के साथ जमीन सौदों में शामिल एच एल पाहवा, संजय भंडारी, सी सी थंपी.. ये तीनों ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच के दायरे में हैं। प्रसाद ने जोर दिया कि कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जमीन वहां के भूखंड दर पर खरीदी गयी थी, तो 15 लाख की जमीन 3 साल 10 महीने बाद ही 84.15 लाख में कैसे बेच दी गई ? भाजपा नेता ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राफेल पर इतनी तल्खियां क्यों रखे हुए हैं, अब ये साफ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय भंडारी एयरबस का भी मिडिल मैन (बिचौलिया) था और एयरबस यूरो फाइटर बनाती है। यही यूरो फाइटर राफेल के लिए टेंडर की प्रतिस्पर्धा में भी शामिल थी। इससे पहले बुधवार का मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से कहा था कि राबर्ट वाड्रा विवादास्पद जमीन सौदे के संबंध में महज मुखौटा हैं और उनके साले राहुल गांधी असली चेहरा हैं। वहीं, इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि हार को भांपते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके चहेते पूरी तरह से बेबुनियाद और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह एच एल पाहवा कौन है जो सभी जमीन लेनदेन में शामिल हैं। इस पर कांग्रेस की खामोशी बड़े सवाल खड़ा करती है। उन्होंने दावा किया कि राबर्ट वाड्रा से संबंधित सभी जमीन घपले में राहुल गांधी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस संदर्भ में जमीन से जुड़े खरीद फरोख्त के कुछ कागजात भी पेश किये उन्होंने कहा कि पलवल में एक मामले में जमीन खरीदने वाले राहुल गांधी हैं और बेचने वाल पाहवा है। एक अन्य मामले में हसनपुर में जमीन खरीदने वाल राबर्ट वाड्रा और बेचने वाला पाहवा है तथा एक अन्य मामले में अमीपुर में जमीन खरीदने वाली प्रियंका वाड्रा और बेचने वाले पाहवा हैं। प्रसाद ने सवाल किया कि जमीन लेनदेन के सभी मामले में जमीन एक ही व्यक्ति से क्यों खरीदी गई ?

४ की मौत, ३० से ज्यादा लोग घायल

मुंबई में सीएसटी स्टेशन के पास गिरा फुट ओवर ब्रिज

घायलों में ४-५ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन्हें गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है

मुंबई । महाराष्ट्र की राज धानी मुंबई में गुरुवार शाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा हुआ है । शुरुआती जानकारी के अनुसार मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज गिरने के कारण ४ लोगों की मौत हुई है । वहीं इस घटना में ३० से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है । इन घायलों में ४-५ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इन्हें गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है । वहीं मलबे में अब भी १० से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई है । मुंबई पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के प्लैटफॉर्म नंबर १ पर बना ब्रिज अचानक गिर गया है । पुलिस के मुताबिक सीएसटी स्टेशन के प्लैटफॉर्म नंबर १ और बीटी लेन के बीच बना एक फुटओवर ब्रिज अचानक गिर गया। इस ब्रिज के गिरने के बाद कई लोग इसकी चपेट में आकर मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद तत्काल मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने आमलोगों की मदद से लोगों को मलबे से निकालने के काम शुरू किया । इसके बाद घायल कई अन्य लोगों को भी रेस्क्यू कर स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। रेलवे के सूत्रों के अनुसार, इस ब्रिज के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसे देखते हुए इलाके में बड़े स्तर पर राहत कार्य शुरू कराए गए हैं। हादसे में ४-५ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही जा रही है, जिन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है । कार्रवाई में एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस की टीम को भी मौके पर लगाया गया है । प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ ब्रिज के नीचे बड़ी संख्या में लोग, वाहन मौजूद थे ।

संपादकीय

निगरानी में कोताही

एक बार फिर देश की शीर्ष अदालत ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब जबकि देश आम चुनावों की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है तब भी उम्मीदवारों की संपत्ति पर निगरानी के लिए कारगर तंत्र क्यों नहीं बनाया जा सका। इस मामले में गंभीर सुप्रीमकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिये दो सप्ताह का समय दिया है। दरअसल, बीते साल सुप्रीमकोर्ट ने चिंता जताई थी कि जनप्रतिनिधि और उनके परिजन ऐसे तौर-तरीके अपनाते हैं कि वे धन-संपदा जुटाने के बावजूद भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के दायरे से बच जाते हैं। जिसके चलते शीर्ष अदालत ने इनकी भ्रष्ट कारगुजारियों पर अंकुश लगाने के लिये सरकार से कहा था कि स्थायी निगरानी के लिये कारगर व्यवस्था करे। साथ ही उम्मीदवार और उनके आश्रितों की आय के स्रोतों की जानकारी जुटाने को कहा गया था। लेकिन अब जबकि सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा हो चुकी है, ऐसी पहल की आवश्यकता तत्काल महसूस की जा रही है। एक सर्वेक्षण में कुछ जनप्रतिनिधियों की आय में सौ प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से सुप्रीमकोर्ट की चिंता से सहमत हुआ जा सकता है। एक गैर सरकारी संगठन की अवमानना याचिका पर चर्चा के दौरान मंगलवार को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए चेताया कि अदालत इस बात का कोई नोटिस जारी नहीं कर रही है मगर वह सरकार का पक्ष सुनना चाहती है कि उसने निगरानी तंत्र तैयार क्यों नहीं किया? आखिर उसने अदालत के निर्णय का पालन क्यों नहीं किया? अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या निर्वाचन के फार्म-26 में संशोधन करके उसमें अयोग्यता का प्रावधान जोड़ा गया है? देश में चुनावों के दौरान जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से भी ज्यादा धन खर्च होने की संभावना है, ऐसे में उम्मीदवारों के पैसा पानी की तरह बहाने के मूल में कहीं न कहीं नंबर दो के स्रोत से आय अर्जित करना भी है। उम्मीदवारों द्वारा अपवित्र संसाधनों से धन जुटाने की ही वजह यह भी है कि देश में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है, जिसके चलते ईमानदार व वाकई योग्य जनप्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं। इसे लोकतंत्र की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि अपवित्र तौर-तरीकों से अर्जित धन संपदा देश में लोकतंत्र की सेहत पर प्रतिकूल असर डाल रही है। इस तरह चुनाव धनबल के भौंडे प्रदर्शन का सबब बनकर रह जाता है।

उम्मीदवारों द्वारा अपवित्र संसाधनों से धन जुटाने की ही वजह यह भी है कि देश में चुनाव लड़ना बहुत महंगा हो गया है, जिसके चलते ईमानदार व वाकई योग्य जनप्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गये हैं। इसे लोकतंत्र की विफलता के रूप में देखा जा सकता है।

चुनावी समर में नई चुनौतियां

अर्थव्यवस्था/ राजीव सिंह

आर्थिक विकास दर के आंकड़ों की गणना पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। यह सच है कि पिछले साल की तुलना में तीसरी तिमाही की जीडीपी में कमी आई है। सरकार इस आंकड़े को किसी भी सूरत में झुठला नहीं सकती क्योंकि यह उसी के द्वारा जारी किए गए हैं। सरकार की चिंता की यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए सवालों की बौछार करेंगे।

चुनावी मौसम में भाजपा नीत मोदी सरकार अपने विकास कायरे को सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जनता के बीच जाकर पार्टी इसी मुद्दे पर वोट मांग रही है। इस दरम्यान आर्थिक विकास को जो आंकड़े आए हैं, उनसे सरकार को बड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर धीमी पड़कर 6.6 फीसद रही है। आर्थिक वृद्धि दर का यह आंकड़ा पिछली पांच तिमाहियों में सबसे कम है। इसके बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी चीन की आर्थिक वृद्धि दर अक्टूबर-दिसम्बर तिमाही में 6.4 फीसद रही है। चिंता की बात यह है कि तीसरी तिमाही का आंकड़ा सरकार के 6.7 फीसद के अनुमान से कम है। इस वजह से उसे वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपने विकास दर के अनुमान को 7.2 फीसद की तुलना में घटाकर सात फीसद करना पड़ा है। इससे पिछले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी वृद्धि 7.2 फीसद रही थी। चुनावी समर के दौरान अर्थव्यवस्था में सुस्ती के आंकड़ों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों पर विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। इनकी ओर से बार-बार यही सवाल पूछा जा रहा है कि मोदी सरकार रोजाना देश में विकास की गंगा बहने का दावा कर रही है तो फिर आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट क्यों आ रही है ? देखा जाए तो विपक्ष के इस सवाल में दम भी है। आर्थिक विकास दर के आंकड़ों की गणना पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। यह सच है कि पिछले साल की तुलना में तीसरी तिमाही की जीडीपी में कमी आई है। सरकार इस आंकड़े को किसी भी सूरत में झुठला नहीं सकती क्योंकि यह उसी के द्वारा जारी किए गए हैं। सरकार की चिंता की यही सबसे बड़ी वजह है क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए सवालों की बौछार करेंगे। सरकार के थिंक टैंक ने विपक्षी हमलों के बचाव के लिए निश्चित तौर तैयारी की होगी। इस बीच उम्मीद की किरण यह है कि तीसरी तिमाही में अचल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर 10.6 फीसद के स्तर पर मजबूत रही। हालांकि सीएसओ ने इसमें पूरे वित्त वर्ष के लिए 10 फीसद की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो इस बात का संकेत है कि सकल अचल पूंजी निर्माण के निवेश में भी मंदी की आशंका है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, आम चुनाव से पहले आचार संहिता की बंदिशें और दूसरा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में नकदी का संकट। हालांकि ये दोनों ही समस्याएं अस्थायी हैं। यदि चुनाव के बाद केंद्र में मजबूत सरकार गठित होती है तो ये दोनों ही समस्याएं जल्द दूर हो सकती हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमारी क्षमता का उपयोग अब भी 74.8 फीसद पर टिका हुआ है, जबकि इसमें वृद्धि की अच्छी संभावनाएं हैं। क्षमता के उपयोग में वृद्धि से विकास दर को रफ्तार दी जा सकती है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचा क्षेत्र को इसकी खासी जरूरत है। अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कारक हैं, जो सरकार की पेशानी पर बल डाल रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के चालू वित्त वर्ष के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार पूरे वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र की विकास 2.7 फीसद रहेगी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में पांच फीसद थी। वोट बैंक की दृष्टि से यह सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। देश की कुल निजी खपत में ग्रामीण क्षेत्र का 45 फीसद योगदान है। हालांकि कृषि क्षेत्र अब ग्रामीण विकास का एकमात्र चालक नहीं रह गया है। फिर भी यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जो देश में 42 फीसद आबादी की रोजी-रोटी का जरिया है और जीडीपी में इसका 15.5 फीसद योगदान है। कृषि क्षेत्र की विकास में गिरावट का सीधा अर्थ है कि खेती पर निर्भर लोग विकास में बाकी आबादी से पिछड़ रहे हैं। ऐसे में कृषि को संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इनके जरिए ही इस क्षेत्र को पटरी पर लाया जा सकता है। दूसरी ओर, नियंतण्र अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट तेज हो गई है। हाल के दिनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जारी हुए आंकड़ों से मंदी की आशंकाओं को बल मिला है। चीन के घटनाक्रम के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की चिंताएं और बढ़ गई हैं। आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए चीन ने प्रोत्साहन के रूप में कई उपाय किए हैं। यह हालात सिर्फ चीन के ही नहीं है। यूरो जोन की अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर से गुजर रही है। यहां की जीडीपी में 1.1 से 1.7 फीसद की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यहां के केंद्रीय बैंक ने सात मार्च को बड़े उपायों का ऐलान किया है। यूरो जोन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में मंदी के दौर से बमुश्किल बच पाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमतें खतरा बनी हुई हैं। हालांकि नवम्बर में ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति डॉलर की ओर पहुंचा था जो अब काफी नीचे आ गया है। इससे सरकार को अपनी वित्तीय सेहत सुधारने में काफी हद तक मिली है, लेकिन ओपेक के उत्पादन में कटौती के संकेतों से तेल की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। इन तमाम जोखिमों के बावजूद वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही से आर्थिक वृद्धि दर में सुधार की उम्मीद बन रही है। मोदी सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में दिवालिया एवं समाधान कानून, जीएसटी, रेरा और कालेधन के प्रवाह पर नकेल कसने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। अर्थव्यवस्था को इन सुधारों का लाभ लंबी अवधि तक मिलेगा। जाहिर है इससे विकास की रफ्तार का दौर लंबे समय तक बनी रहेगी। इसके बावजूद सरकार को भूमि सुधार, श्रम सुधार और कृषि बाजार को मुक्त करने की दिशा में और व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। बुनियादी ढांचा और कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना समय की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करना जरूरी है। उम्मीद है कि चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार इन मुद्दों को अपनी प्राथमिकता में शामिल करेगी। यदि इस दिशा में गंभीरता से विचार नहीं किया गया है नियंतण्र अर्थव्यवस्था में व्याप्त संकट की तपिश से बच पाना मुश्किल हो जाएगा।

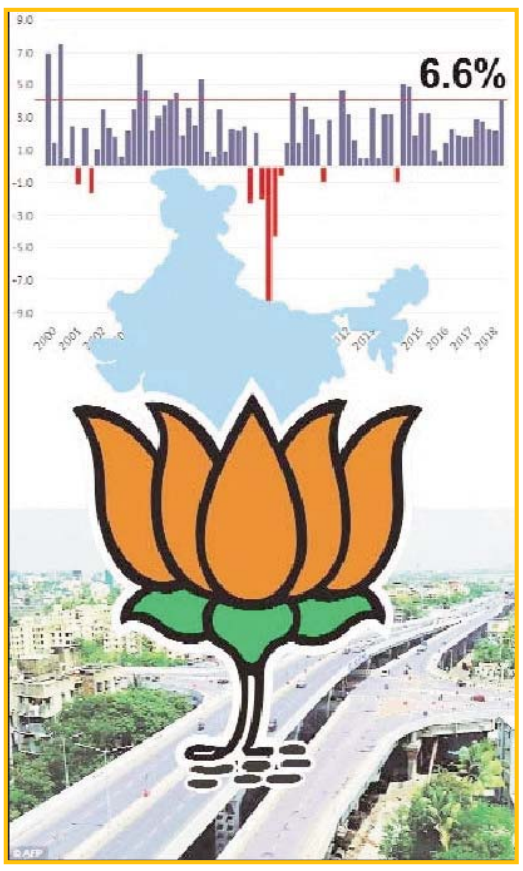

आज का राशीफल

मेष व्यावसायिक योजना को बल मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें, दुर्घटना की आशंका है।

वृषभ सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी अपेक्षित है।

मिथुन जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। चली आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कर्क आर्थिक दृष्टि से लाभदायी है। व्यावसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। स्थानान्तरण का भी लाभ मिल सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा।

सिंह व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्थानान्तरण सुखद हो सकता है। नई नौकरी या नवीन वाहन का सुख मिल सकता है। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रणय प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा।

कन्या आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा।

तुला पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

वृश्चिक जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। विरोधी सक्रिय होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी।

धनु राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। नेत्र विकार की संभावना है। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा।

मकर व्यावसायिक योजना सफल होगी। रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। वाद विवाद की स्थिति कष्टकारी होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

कुम्भ आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आपकी राशि से आठवें शनि यात्राएं देगा व थकान देगा। किसी वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन व्यय होगा।

मीन आर्थिक योजना फलीभूत होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। निजी सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी।

इस युद्ध को जनतंत्र के उत्सव में बदलें

आम चुनाव/ विश्वनाथ सचदेव

जनतंत्र में चुनाव युद्ध नहीं होता। यह सही है कि चुनाव में अलग-अलग पक्ष होते हैं। हर पक्ष के पास अपने 'अस्त्र-शस्त्र' होते हैं, अपने दावे, अपने वादे, अपना सच, अपना झूठ। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो दोनों पक्षों के रथियों-महारथियों ने अपने-अपने शंख बजाकर युद्ध के लिए अपनी तैयारी की घोषणा की थी। कुछ-कुछ वैसा ही दृश्य आज देश में दिख रहा है। चुनाव-आयोग द्वारा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने घोषणाएं शुरू कर दी हैं। व्यूह-रचनाओं में जुटे हुए हैं सब दल। अपनी कमज़ोरियों को छिपाने और दूसरे की कमज़ोरियों को उजागर करने की होड़-सी लगी हुई है। एक-दूसरे के रथियों को अपने पाले में लाने में भी किसी को किसी प्रकार का संकोच नहीं दिख रहा है। यह लड़ाई अगले लगभग दो माह में क्या-क्या गुल खिलाती है, यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, पर इतना तो अभी से पता चलने लगा है कि इस लड़ाई में भी सब कुछ जायज़ है, की लीक को पीटा जायेगा। हर चुनाव में इसी तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। बात ईमानदार लड़ाई की, की जाती है और सारी चालें बेईमानी के संकेत देती हैं। झूठे वादे, झूठे दावे, झूठे आरोपज् सच कहीं खो जाता है इस धमाचौकड़ी में। और वह सच यह है कि जनतंत्र में चुनाव युद्ध नहीं होता। चुनाव उत्सव है जनतंत्र का। युद्ध में सिर्फ जीतने वाला खुशी मनाता है, लेकिन चुनाव में सब खुशी मनाते हैं। आज़ादी पाने के बाद से लेकर अब तक के चुनावों में पहले दो चुनाव ही शायद कुछ अपवाद थे। सन ् 57 के बाद जितने भी चुनाव देश में हुए हैं, उन्हें उत्सव की नहीं, युद्ध की भावना से ही लिया गया है। लेकिन, जनतंत्र में चुनाव की महत्ता को देखते हुए इस हकीकत को बदलने की ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए। मतदाता को महसूस होनी चाहिए ये ज़रूरत। राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता हथियाने की लड़ाई लड़ते हैं। यह दायित्व मतदाता का बनता है कि वह इस लड़ाई को उत्सव में बदलने के पक्ष में खड़ा दिखे। यह देखना उसका काम है कि कौन-सा सैनिक इस लड़ाई में अनुचित बर्ताव कर रहा है। चुनाव यदि लड़ाई है तो यह सच और झूठ के बीच होनी चाहिए, उचित और अनुचित के बीच होनी चाहिए। मतदाता इस लड़ाई का मूकदर्शक नहीं होता, उसकी सक्रिय भूमिका है लड़ाई को उत्सव में बदलने के इस काम में। मतदाता, यानी मेरा और आपका दायित्व बनता है कि हम राजनीतिक दलों की कथनी और करनी पर नज़र रखें। जागरूकता के सारे तकाज़ों के बावजूद यह सही है कि मतदाता की याददाश्त कमज़ोर होती है। इसलिए आज यह जरूरी है कि हम चुनाव के मैदान में खड़े शूरवीरों से उनके कहे-किये का हिसाब पूछें। सत्तारूढ़ पक्ष से हमें यह पूछना है कि पिछले चुनाव में जो सपने उसने दिखाये थे, वे कितने पूरे हुए? हमने देखा था कि पिछला चुनाव, तब के विपक्ष ने, भ्रष्टाचार को मिटाने और विकास के नारे पर लड़ा था। हमें देखना यह है कि भ्रष्टाचार और विकास के इन वादों को पूरा करने के लिए सत्तारूढ़ पक्ष ने क्या-कुछ किया, इस बारे में उसके दावे कितने सच्चे हैं। देखना है कि चुनावों के इस मौके पर उसकी भाषा बदल तो नहीं रही। जो सामने दिख रहा है, वह यह है कि सत्तारूढ़ पक्ष अब भ्रष्टाचार-मुक्त देश की बात नहीं कर रहा, 'अच्छे दिन' लाने की बात भी नहीं हो रही। अब इन सबका स्थान 'तीव्र राष्ट्रवाद' के नारों ने ले लिया है। अचानक देश-भक्ति और देशद्रोह की बातें ज़ोरों से होने लगी हैं। इन बातों पर गंभीरता से सोचना होगा मतदाता को। झूठे दावे विपक्ष भी करता है। इन दावों को भी नापा-तोला जाना चाहिए।

हमारे जनतंत्र की एक त्रासदी यह भी है कि हमारी राजनीति में नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं दिख रही। नैतिकता का एक मतलब यह भी है कि हमारे राजनेता और राजनीतिक दल अपनी घोषित नीतियों और सिद्धांतों के प्रति कितने ईमानदार हैं। बरसों पहले शुरू हुआ था हमारी राजनीति में 'आया राम, गया राम' का किस्सा। वह आज भी चल रहा है। अंतर यदि है तो सिर्फ यह कि पहले इसे अनैतिक कहा गया था, पर अब इस संदर्भ में किसी नैतिकता की आवश्यकता ही नहीं महसूस की जाती। दलबदल करना कपड़े बदलना जैसा हो गया है। अपना दल छोड़ने में किसी को कोई संकोच नहीं होता और किसी राजनीतिक दल को भी आज इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि आज वह जिस राजनेता का हार पहनाकर स्वागत कर रहा है, कल तक वह उसे गालियां दिया करता था।

आज देश में राजनीतिक शुचिता की कोई बात नहीं होती। राजनेता सिर्फ सत्ता की राजनीति का खेल खेलते हैं। यह खेल उनके लिए युद्ध है। यह युद्ध किसी भी कीमत पर जीतना उन्हें महंगा नहीं लगता। कभी वे धर्म का पत्ता खेलते हैं, कभी जाति का। जनतंत्र की सार्थकता की सबसे बड़ी शर्त मतदाता की जागरूकता है- चुनाव इस जागरूकता को प्रमाणित करने का सबसे बड़ा अवसर!

भारतीय लॉन टेनिस के लिए बंध रही नई उम्मीदें

मनोज चतुर्वेदी, वरिष्ठ खेल पत्रकार

भारतीय टेनिस ने दुनिया को रामनाथन कृष्णन, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन और लिएंडर पेस जैसे दिग्गज खिलाड़ी दिए हैं। इनमें हम यदि पेस को छोड़ दें, तो बाकी सभी का सिंगल्स में शानदार प्रदर्शन रहा है। इन सभी खिलाड़ियों के उभरने के समय में काफी अंतर है और यह अंतर एक दशक तक का है। यह बताता है कि हमें लगातार बड़ी प्रतिभाएं नहीं मिली हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले एक दशक में जितने भी खिलाड़ियों ने टेनिस में थोड़ी-बहुत चमक बिखेरी है, वे सभी विदेशों में ट्रेनिंग लेने के बाद ही इस लायक बने। इनके अलावा सोमदेव देववर्मन और युकी भांबरी भी टॉप 100 में हैं, पर ये दोनों ही इस स्थिति में ज्यादा देर टिके नहीं रह सके। इस कड़ी में ही नया नाम जुड़ा है प्रजनेश गुणोरन का। प्रजनेश ने अभी कुछ ही समय पहले 97वीं रैंकिंग हासिल की थी। इसके बाद इंडियन वेल्स में हुए बीएनपी पारिबास टेनिस टूर्नामेंट में तीसरे राउंड में इवो कार्लोविच से हारने के पहले उन्होंने 17वीं सीड निकोलोज बासिलशविली और इससे पहले 13वीं रैंकिंग तक पहुंच चुके बेनोइट पेयरे को हराकर यह तो दिखा दिया है कि उनमें टिके रहने का माद्दा है। इन प्रदर्शन के बाद अगले हफ्ते उनकी रैंकिंग में और सुधार संभव है। प्रजनेश का लक्ष्य इस साल किसी समय पहले 50 खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराना है। संन्यास लेने के बाद भी लगातार टेनिस से जुड़े रहने वाले विजय अमृतराज ने जब प्रजनेश को इंडियन वेल्स में खेलते देखा, तब उन्हें वह टॉप 50 वाला मेटीरियल नजर आए। हम यदि पिछले कुछ सालों को देखें, तो देश को डबल्स में तो पेस के अलावा महेश भूपति और रोहन बोपन्ना जैसे दिग्गज खिलाड़ी मिले, लेकिन सिंगल्स में विश्व स्तरीय खिलाड़ी मिलने में लगातार दिक्कत हो रही है। मौजूदा टेनिस का पावर गेम में बदल जाना भी इसकी वजह हो सकती है। युगल में तो दो खिलाड़ियों के बीच जिम्मेदारी बंट जाने से इसमें इस्तेमाल होने वाली ताकत का स्तर कुछ कम हो जाता है, लेकिन सिंगल्स में खेलने के लिए अतिरिक्त फिटनेस की जरूरत पड़ती है। मौजूदा समय में टेनिस खेलने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा दमखम की जरूरत पड़ती है। आयोजकों ने खेल को बेचने के वास्ते लंबी रैलियां करने के लिए गेंद का वजन बढ़ा दिया और कोर्ट की तेजी को कम कर दिया, जिससे खिलाड़ियों को अंक पाने के लिए ज्यादा जूझना पड़ता है। कहा जाता है कि यूरोपीय और अमेरिकी खिलाड़ियों की तुलना में भारतीय खिलाड़ियों के शरीर की संरचना की अपनी सीमाएं हैं। वे जब अतिरिक्त फिटनेस के लिए प्रयास करते हैं, तो शरीर धोखा दे जाता है। इसे हम महेश भूपति के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। भूपति ने करियर के शुरुआती दिनों में एक विदेशी ट्रेनर रखा था। उसने शरीर पुश करने के लिए उन्हें बहुत दौड़ाया, जिससे वह हैमस्ट्रिंग का शिकार बन गए। यह उनके शरीर के बोझ न ले पाने के कारण हुआ। प्रजनेश की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई, लेकिन प्रजनेश की कभी न हार मानने वाली प्रवृत्ति उन्हें निरंतर आगे ले जा रही है। एक समय था, जब उन्होंने पांच साल तक भारतीय सर्किट में खेला ही नहीं और लगातार चोट की समस्या करियर को मुश्किल में डाल रही थी। हालांकि वह अमेरिका में कॉलेज टेनिस खेलते रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ साल पहले जर्मनी की अलेक्जेंडर वास्के अकादमी में ट्रेनिंग ली।

जिसके बाद प्रजनेश की बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई। प्रजनेश के साथ ही इस समय भारतीय टेनिस में दो और सिंगल्स खिलाड़ी युकी भांबरी और रामकुमार रामनाथन अपना जलवा बिखेर रहे हैं। युकी भांबरी इन तीनों में सबसे पहले टॉप 100 में पहुंचने वाले थे, लेकिन जल्द ही ताकत के जवाब देने से वह पिछड़ गए। रामकुमार रामनाथन 111वीं रैंकिंग तक पहुंचने के बाद अब 133वीं रैंकिंग पर हैं। ये तीनों ही टॉप 100 में आ जाएं, तो माना जा सकता है कि भारतीय टेनिस की तकदीर बदल सकती है। नए खिलाड़ियों के आने का सिलसिला जारी रहे, इसके लिए देश में ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी कि युवाओं को शुरुआती ट्रेनिंग के लिए विदेश न जाना पड़े।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

घर खरीदने वालों को होली का तोहफा देगी सरकार

बिजनेस डेस्क।

चुनाव से पहले 19 मार्च को जीएसटी कार्उंसिल की बैठक होना तय है। 24 फरवरी को हुई बैठक में जीएसटी कार्उंसिल रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत दी थी। जीएसटी कार्उंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर टैक्स की दरों को घटाकर 5 फीसदी कर दिया था साथ ही अफोर्डेबल घरों पर जीएसटी की दर को घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। इससे पहले अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर 12 फीसदी और अफोर्डेबल घरों पर 8 फीसदी जीएसटी लग रहा था। जीएसटी कार्उंसिल ने नई दरों को 1 अप्रैल 2019 से लागू करने को मंजूरी दी थी साथ ही लोगों को इसका फायदा देने के लिए विस्तृत गाइडलाइन अगली बैठक में जारी करने की बात कही थी। अब जीएसटी कार्उंसिल 19 मार्च को होने वाली बैठक में रियल्टी सेक्टर में जीएसटी दरें कम करने का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगी। यह गाइडलाइन जारी होने के बाद तय हो जाएगा कि आप कैसे सस्ता घर खरीद सकते हैं। जानकारों का कहना है कि होली से पहले गाइडलाइन जारी होने से घर खरीदने वालों को राहत जरूर मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी दरें कम होने से पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह सुनहरा मौका है। अगर आप पहली बार घर अंडर कंस्(ट्रक्(शन प्रोजेक्(ट में फ्लैट खरीद रहे हैं तो अभी तक 12 फीसदी की दर से जीएसटी का भुगतान करना होता है।

वहीं एक अप्रैल से यह दर घटकर 5 फीसदी हो जाएगी। यानी जीएसटी में 7 फीसदी की कमी। इसके चलते 45 लाख रुपए की प्रॉपर्टी पर 3.15 लाख रुपए की सीधे बचत होगी। अगर आप पहली दफा घर खरीदने जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत होम लोन पर 2.67 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इस तरह कुल 5.82 लाख रुपए की बचत होगी।

भारतीय इतिहास के सबसे बड़े दानी बने अजीम प्रेमजी, 52750 करोड़ रुपए के शेयर किए दान

बिजनेस डेस्क।

आईटी दिग्गज और विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने विप्रो लिमिटेड के 34 फीसदी शेयर परोपकार के लिए देने का फैसला किया है जिसका बाजार मूल्य 52,750 करोड़ रुपए है। अजीम देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो के चेयरमैन हैं। वह अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जरिए लोगो की मदद करने का काम करते हैं। इसमें वह अब तक 1.45 लाख करोड़ रुपए दे चुके हैं। दिसंबर 2018 में विप्रो में प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी 74.3त्न थी। अब तक इतनी राशि किसी भी दानी ने दान नहीं की जिस कारण अजीम प्रेमजी इतिहास के सबसे बड़े दानी बन चुके है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने बयान में कहा कि अजीम प्रेमजी ने अपनी निजी संपत्तियों का त्याग कर, उसे धर्मार्थ कार्य के लिए दान कर परोपकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाई है।अजीम फाउंडेशन दुनिया की बड़ी फाउंडेशन की सूची में शुमार है। 73 वर्षीय प्रेमजी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने द गिविंग प्लेज इनीशिएटिव पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल की शुरुआत बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने की थी जिसके तहत अपनी 50 फीसदी संपत्ति परोपकारी कार्य के लिए देने का वादा किया जाता है। समाजसेवा के लिए बनाया गया अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मुख्यत= शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। इसका लक्ष्य पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाना है। फाउंडेशन इस क्षेत्र में काम करने वाले कई एनजीओ को आर्थिक मदद भी देता है।

अजीज प्रेमजी फाउंडेशन कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राज्यों में सक्रिय है। वंचित तबकों के लिए काम कर रहे 150 से ज्यादा एनजीओ को 5 साल में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से फंड मिला है।

एयर इंडिया 16 मार्च से रोकेंगी दिल्ली-मैड्रिड, दिल्ली-बिर्मिंघम की उड़ान

बिजनेस डेस्क ।

एयर इंडिया ने दिल्ली-मैड्रिड और दिल्ली-बिर्मिंघम मार्गों पर ''परिचालनगत कारणों के चलते'' अपनी उड़ानें 16 मार्च से अगले आदेश तक रोक देने का ऐलान किया है। भारतीय वायु सेना की बालाकोट एयर स्ट्राइक के कारण पाकिस्तान ने 26 फरवरी से अपना वायु क्षेत्र बंद कर रखा है। इसकी वजह से यूरोप और अमेरिका के लिए उड़ानों पर एयर इंडिया का खर्च बढ़ गया है। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने कहा ''परिचालनगत कारणों से एयर इंडिया की उड़ानें 16 मार्च 2019 से अगले नोटिस तक रोकी जा रही हैं। आगे एयरलाइन ने कहा है कि एआई 135 दिल्ली-मैड्रिड उड़ान और एआई 136 मैड्रिड-दिल्ली उड़ान रोकी जाएंगी। एयर इंडिया ने कहा है कि एआई 113 दिल्ली-बिर्मिंघम उड़ान और एआई114 बिर्मिंघम-दिल्ली उड़ान को भी रोका जाएगा साथ ही एयरलाइन ने कहा कि एआई 117 दिल्ली-अमृतसर-बिर्मिंघम उड़ान और एआई 118 बिर्मिंघम-अमृतसर-दिल्ली उड़ान को भी रोका जाएगा। इस फैसले से यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए एयरलाइन ने उनसे रिफंड की राशि लेने की अपील की है।

रिलायंस ने अमेरिकी प्रतिबंध के मद्देनजर वेनेजुएला को तेल निर्यात किया बंद

नई दिल्ली।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को कहा कि उसने वेनेजुएला को उसके खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंधों मद्देनजर तेल निर्यात बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा कि प्रतिबंधों को हटाए जाने तक निर्यात बंद रहेगा। कंपनी के जामनगर परिशोधन संयंत्र ने वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद भी करीब एक तिहाई कम कर दी है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, ''अमेरिकी सरकार द्वारा वेनेजुएला की सरकार पर जनवरी 2019 में लगाए प्रतिबंधों के बाद से इनका पूरा अनुपालन करने के लिए कंपनी अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में है।'' प्रवक्ता ने कहा, ''हमारी अमेरिकी अनुषंगी ने वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पीडीवीएसए के साथ सारा कारोबार बंद कर दिया है और इसकी वैश्विक मूल कंपनी ने कच्चा तेल की खरीदको बढ़ाया नहीं है।''

उसने कहा, ''प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से रिलायंस ने कुछ खबरों के उलट पीडीवीएसए को थिनर की आपूर्ति बंद कर दी है और इसे तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिबंध लागू रहेगा।'' कंपनी ने कहा कि वह प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए अमेरिकी सरकार से रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे। कंपनी ने कहा कि वह प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए अमेरिकी सरकार से रचनात्मक बातचीत जारी रखेंगे।

संक्षिप्त समाचार

चांदी 410 रुपए सस्ती-सोना 15 रुपए फिसला

नई दिल्ली । वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही भारी गिरावट के बीच जेवराती माँग की सुस्ती से दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 15 रुपये फिसलकर 33,370 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। इस दौरान औद्योगिक ग्राहकी कमजोर पडने से चाँदी भी 410 रुपये लुढ़ककर 39,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर के मजबूत होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीली धातु पर दबाव बढ़ा है। लंदन का सोना हाजिर 7.85 डॉलर लुढ़ककर 1,301.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। अप्रैल का अमेरिकी सोना वायदा भी 7.30 डॉलर की गिरावट के साथ 1,302.00 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने से अन्य मुद्राओं वाले देशों के लिए सोने का आयात महंगा हो जाता है। इससे सोने की माँग घटती है और कीमत में गिरावट आती है। विदेशी बाजारों में चाँदी हाजिर भी 0.15 डॉलर लुढ़ककर 15.27 डॉलर प्रति औंस पर आ गयी।

फरवरी में थोक मुद्रास्फीति बढ़कर हुई 2.93 प्रतिशत

बिजनेस डेस्क। ईंधन, बिजली एवं प्राथमिक वस्तुओं की कीमतें बढने से फरवरी महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 2.93 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

बृहस्पतिवार को जारी सरकारी आंकड़ों में इसकी जानकारी दी गयी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 2.76 प्रतिशत थी। पिछले साल फरवरी माह में यह 2.74 फीसदी थी। आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर जनवरी के 3.54 प्रतिशत की तुलना में फरवरी में बढ़कर 4.84 प्रतिशत पर पहुंच गयी। प्राथमिक वस्तुओं में आलू, प्याज, फल और दूध जैसे रसोई के आवश्यक सामान शामिल हैं। इस दौरान ईंधन एवं बिजली की मुद्रास्फीति 2.23 प्रतिशत बढ़ गयीं। जनवरी महीने में इसमें 1.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

बोइंग 737 मैक्स बैनः हवाई यात्रियों पर दोहरी मार,किराया 50फीसदी तक बढ़ा

नई दिल्ली। हवाई यात्रियों की जेब पर इन दिनों भारी मार पड़ रही है। मुंबई-दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हवाई किराये में इस साल 50 फीसदी तक का उछाल आया है और अब बोइंग मैक्स-8 विमान बैन होने की वजह से और जोर का झटका लगना तय है। स्पाइसजेट के 13 और जेट एयरवेज के 5 बोइंग 737 मैक्स 8 विमान बैन होने से फ्लाइट की संख्या में और कमी आ गई है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए के भारत में बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान रोकने के फैसले के बाद 18 विमान जमीन पर आ जाएंगे। जेट एयरवेज में संकट की वजह से पहले ही देश की चौथे नंबर की एयरलाइन्स ने बहुत सी उड़ानें कम कर दी हैं। जिसकी वजह से दिल्ली-मुंबई के किराए सबसे ज्यादा बढ़े हैं। इसी तरह दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-हैदराबाद के भी किराए करीब 40 परसेंट बढ़े हैं। जाहिर है कि ऐसे समय में बोइंग 737 मैक्स विमानों की उड़ान पर रोक से हवाई किराए और बढ़ने तय हैं। हाल ही में इथियोपियन एयरलाइन्स के एक प्लेन के क्रैश होने के बाद दुनियाभर में बोइंग 737 मैक्स विमानों को लेकर चिंताएं पैदा हो रही है। दरअसल इस हादसे में क्रैश होने वाला प्लेन बोइंग 737 मैक्स 8 था। इस प्लेन क्रैश में 4 भारतीयों सहित सभी 157 लोगों की मौत हो गई। इन लोगों में से 149 यात्री थे, जबकि बाकी 8 क्रु मेंबर थे।

ई-कॉमर्स कंपनियों ने बनाया शीर्ष संगठन, फ्लिपकार्ट-अमेजन को नहीं किया शामिल

नयी दिल्ली । देश में तेजी से बढ़ रहे ई कॉमर्स कारोबार के बीच इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों ने अपना शीर्ष संगठन 'द ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ़ इंडिया' (टेसी) बनाया है लेकिन इसके संस्थापक सदस्यों में प्रमुख ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट शामिल नहीं हैं। टेसी के संस्थापक सदस्यों में स्नैपडील, शॉपक्लूज़, अर्बनक्लैप, फ्लायरोब, फाइंड, सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म शॉप101, बेवकूफ डॉटकॉम, ब्रेया, रस्टऑरेंज, ममाअर्थ, सुपरबॉटम्स और अज़ा शामिल हैं। टेसी ने बुधवार को यहां जारी बयान में कहा कि उसके सदस्यों के पास 7.5 लाख से अधिक ऑनलाइन विक्रेता और सेवा प्रदाता शामिल हैं। हर महीने टेसी के सदस्यों द्वारा परिचालित ऑनलाइन कारोबार से 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ता जुड़ते हैं। टेसी के सदस्यों द्वारा स्थापित उपक्रमों में 30 से अधिक वैश्विक एवं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2.25 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है। भारतीय ई कॉमर्स उद्योग के लिए नीतिगत पैरोकारी के साथ ही टेसी डाटा गोपनीयता, लॉजिस्टिक, भुगतान , विवादों के निपटान, उपभोक्ता संरक्षण, एमएसएमई विकास और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर भी काम करेगा।

बोइंग के मैक्स विमानों को परिचालन से हटाने का बीमा कंपनियों पर नहीं होगा कोई असर

बिजनेस डेस्क। दुर्घटनाओं के कारण विवादित बोइंग 737 मैक्स8 विमानों को परिचालन से हटाये जाने के कारण उन घरेलू बीमा कंपनियों पर कोई असर नहीं होगा जिन्होंने इन विमानों को बीमा मुहैया कराया है। बीमा जगत के अधिकारियों ने यह कहा है। इथियोपिया में रविवार को बोइंग 737 मैक्स8 का एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 157 लोगों की मौत हो गयी थी। इसके बाद से देश की विभिन्न विमानन कंपनियां बोइंग 737 मैक्स8 विमानों को परिचालन से हटा रही हैं। स्पाइसजेट ने 12 बोइंग 737 मैक्स8 विमानों को खड़ा कर दिया है। एक सरकारी बीमा कंपनी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बोइंग 737 मैक्स8 विमानों को खड़ा किये जाने से बीमा कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक निजी बीमा कंपनी के अधिकारी ने कहा कि बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान अग्रिम मिल जाता है तथा उन्हें भुगतान सिर्फ तभी करना होता है जब परिचालन के दौरान कोई नुकसान या दुर्घटना होती है। उसने कहा कि जब विमान खड़े किये जा चुके हैं ऐसे में कोई दावा किये जाने की उम्मीद कम है।

कर्ज में डूबी रुचि सोयाबीन की पंतजलि आर्युवेद ने लगाई बोली

नई दिल्ली।

देश की सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक रुचि सोया की बोली लगाई गई है। आयुर्वेदिक गुरु बाबा रामदेव ने कंपनी को निशचित मुल्य से 200 करोड़ रुपए ज्यादा ऑफर किये हैं। रुचि सोया भारत में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पाद करने वाली कंपनी है। कंपनी के कई उत्पादन प्लांट है और इसके प्रमुख ब्रांडों में न्यूट्रेला, महाकोश, सनरिच, रूचि स्टार और रूचि गोल्ड शामिल हैं। कंपनी को देश की संपति भी माना जाता है। अडानी विल्मर की सोया कंपनी पिछले लंबे समय से पंतजलि के साथ विवादों चलते हुए वर्ष 2017 अगस्त में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी। लेकिन कंपनी के दिवालियापन प्रक्रिया को देरी से पूरा करने की बजह से यह दौड़ में पीछे रह गई है। क्योंकि रुचि सोयाबीन कंपनी पर कुल 12,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। दिसंबर 2017 में विल्मर द्वारा कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस के लिए इंदौर स्थित रूचि सोया इंडस्ट्री जएनएस को संदर्भित किया गया था। शैलेन्द्र अजमेरा को एनसीएलटी द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत लेनदारों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और डीबीएस बैंक के आवेदन पर रिज़ॉल्यूशन पेशेवर (आरपी) नियुक्त किया गया था। पंतजलि का कहना है कि रुची सोया को खरीदने और बोली लगाने का फैसला किसानो और ग्राहकों के हित के लिए लिया है। सूत्रो के मुताबिक पतंजलि के संशोधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) अगले हफ्ते बैठक कर सकती है। पतंजलि आयुर्वेद ने एनसीएलटी से रूचि सोया के उधारदाताओं के फैसले की चुनौती देते हुए कहा है ।

कि अदानी विल्मार 6,000 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी देने के लिए तैयार है। लेकिन पतंजलि समूह ने 5,700 करोड़ रुपए की बोली के साथ दूसरे स्थान पर आया है। जिसमें खाद्य तेल कंपनी में लगभग 1,700 करोड़ रुपए का जलसेक शामिल है।

विनिर्माण कंपनियों का शुद्ध मुनाफा तीसरी तिमाही में 25 प्रतिशत बढ़ाः रिजर्व बैंक

मुंबई। विनिर्माण क्षेत्र की निजी कंपनियों का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 24.90 प्रतिशत बढ़ा है। इसका कारण कर की कम दरों के प्रावधान हैं। रिजर्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। रिजर्व बैंक ने कहा कि वित्त क्षेत्र से इतर 2,703 सूचीबद्ध निजी कंपनियों के तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। रिजर्व बैंक ने निजी कंपनियों के प्रदर्शन के बारे में हालिया आंकड़ा जारी करते हुए कहा, ''वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में कर के कम प्रावधानों से विनिर्माण क्षेत्र को लाभ हुआ है और उनका शुद्ध मुनाफा रिकॉर्ड वृद्धि को बरकरार रखे हुए है।'' रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में इन कंपनियों का सम्मिलित शुद्ध मुनाफा 77,500 करोड़ रुपए रहा जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 57,800 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 71,900 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि आलोच्य तिमाही के दौरान सालाना आधार पर विनिर्माण कंपनियों की बिक्री में कमी आई है। रिजर्व बैंक ने कहा, ''कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, मोटर वाहन और अन्य परिवहन उपकरणों के क्षेत्र में सुधार दर्ज किया गया जबकि उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्रों जैसे खाद्य उत्पाद और पेय तथा दवा क्षेत्र में बिक्री में तेजी दर्ज की गई।'' आलोच्य तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के ब्याज की लागत में कमी आई। आलोच्य तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र के ब्याज की लागत में कमी आई। रिजर्व बैंक ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में बिक्री की वृद्धि दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में अपरिवर्तित रही है। सेवा क्षेत्र के परिवहन तथा भंडारण सेवा उद्योग में सुधार के कारण बिक्री में वृद्धि की गति बरकरार रही है। रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार क्षेत्र में बिक्री में कमी आई है। आईटी क्षेत्र में शुद्ध मुनाफा मामूली गिरा है।

भारत और चीन ने प्रदूषण से जूझने के लिए तैयार किया स्थायी विकास मॉडल

नई दिल्ली।

भारत और चीन ने देश के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। दुनिया में भारत और चीन को आर्थिक विकास के मामले में सबसे आगे माना जाता है। अब दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए नए मॉडल तैयार किये है। जो कि जलवायु परिवर्तन से आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए मदद करेगें। दोनों देश जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठाकर वैश्विक नेता बन चुके हैं। आर्थिक रणनीतियों में जलवायु कार्रवाई को शामिल कर, वह वैश्विक दक्षिण में विकास के नए तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारे देश अनोखी विकास चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जैसे की वायु प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष एक मिलियन से अधिक मौतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोनों देश अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के साथ ऊर्जा की बढ़ती मांग को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी बढ़ती हुई संपत्ति को अपनी आबादी के व्यापक प्रतिशत तक फैलाना चाहते हैं।

इन्होंने प्रति व्यक्ति आधार पर कार्बन उत्सर्जन कम किया है, लेकिन पेरिस समझौते के लिए उनकी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में उन्हें सीमित करने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन जलवायु परिवर्तन का जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक चालक की सीट ले रहा है। पेरिस समझौते के तहत, चीन ने 2030 तक अपने उत्सर्जन को चरम पर पहुंचाने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा अगले पांच साल की शुरुआत में किया जा सकता है। चीन नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक निवेश करता है। इसने 2016-2020 से 360 मिलियन डॉलर को अक्षय ऊर्जा में डालने की योजना बनाई है। चीन शहरों के पास कोयला जलाने से दूर जाकर और सार्वजनिक परिवहन में निवेश करके वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए प्रगति कर रहा है। लक्ष्य 2020 तक सड़कों पर 4.6 मिलियन शून्य-उत्सर्जन वाहन सकते है, और 2040 तक पारंपरिक दहन इंजन को चरणबद्ध किया जा सकता है। यह वैश्विक कार उद्योग को रीमेक कर सकता है। अपनी स्वच्छ ऊर्जा पहल के परिणामस्वरूप, 2016 से 2017 तक 338 शहरों में 6.5 प्रतिशत से कण मामले को सफलतापूर्वक कम कर दिया। भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए मोर्चे का नेतृत्व किया है, और भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी 40 प्रतिशत बिजली उत्पन्न करने और 2030 तक अपनी कार्बन तीव्रता को 33-35 प्रतिशत कम करने का वादा किया है।

सरकार के पास कई प्रमुख नीतियां हैं जो प्रदर्शन और जलवायु विकास के प्रयासों का आधार पर हैं। जैसे कि उपलब्धि और व्यापार योजना, स्वच्छ पर्यावरण उपकर, और ऊर्जा संरक्षण भवन कोड आदि। इन नीतियों पर निरंतर और सुधार करके, भारत 6-7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को बनाए रखने में अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।

गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 210 ऐडवेयर ऐप्स, हो जाएं सावधान

नई दिल्ली ।

गूगल ने एक बार फिर से खतरनाक ऐप्स पर शिकंजा कसा है। कंपनी ने प्ले स्टोर से 210 ऐप्स हटा दिए हैं। हालांकि कंपनी ने खुद से ऐसा नहीं किया, बल्कि सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने कंपनी को ध्यान दिलाया की ये ऐप्स खतरनाक हैं। ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर गेम, टीवी और रिमोट कंट्रोल सिमुलेटर ऐप्स के तौर पर थे। सिक्योरिटी फर्म चेक प्वॉइंट के रिसर्चर्स ने पता लगाया था कि ये ऐप्स दरअसल ऐडवेयर से प्रभावित थे। ऐडवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पॉप के जरिए खुद से आपको विज्ञापन दिखाते हैं और इसके लिए किसी परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। ये दरअसल कंप्यूटर्स के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन अब स्मार्टफोन में भी ऐसे ऐप्स मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये एंड्रॉयड ऐडवेयर दुनिया भर के 15 करोड़ डिवाइस में पाए गए हैं।

इस कथित मैलवेयर को कुछ मोबाइल गेमिंग के लिए बनाया गया था जिनमें शामिल हैं। इनमें से हर ऐप्स पांच मिलियन बार से ज्यादा डाउनलोड किए गए हैं। जबकि इनमें से एक 10 मिलियन से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। ऐसे करके टोट 210 ऐप्स मिले थे जिन्हें गूगल ने अब प्ले स्टोर से हटा लिया है। एक सवाल ये भी उठता है कि बार बार गूगल प्ले स्टोर के साथ ही ऐसा क्यों होता है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स अपलोड होने से पहले कंपनी इसका रिव्यू करती है और इसके लिए भी प्रोसेस हैं।

लेकिन माना ये जाता है ये गूगल का रिव्यू प्रोसेस अभी भी ऐपल के रिव्यू प्रोसेस से कमजोर है। इसलिए ऐपल ऐप स्टोर में ऐसी दिक्कतें हमेशा नहीं आती हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में भी इस तरह के ऐप्स हैं ।

सूरत। हीरे के व्यापारी के घर लड़की के जन्म पर 121 किलों का पान बोम्बे के सिद्धी विनायक मंदिर में चढाया।

सूरत। शहर के पुणा गाम क्षेत्र के लोगों द्वारा पुणा गाम में जगह जगह पोस्टर लगा कर इस क्षेत्र में सांसद और धारा सभ्य को आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन पोस्टरों पर लोगों द्वारा लिखा गया है कि पिछले पांच साल से सांसद और धारा सभ्य ने हमारे क्षेत्र में आकर किसी भी प्रकार के विकास कार्यो को नहीं किया जिससे लोग इन पर काफी गुस्से में और उन्होने कहा कि अगर सासंद और धारा सभ्य पुणागाम में आते है और उनके साथ कोई घटना होती है तो इसकी संपुर्ण जवाबदारी उनकी होगी न की गांव वालों की।

सामने आये छबील पटेल को लेकर कई सवाल

भानूशाली हत्या केस में छबील पटेल की गिरफ्तारी

आत्मसमर्पण करने के लिए गुजरात में मुख्यमंत्रीपद के दावेदार केंद्र के नेता ने ऑपरेशन किए जाने की चर्चा

अहमदाबाद । भाजपा के नेता और पूर्व विधायक जयंती भानूशाली की जनवरी -२०१९ में चल रही ट्रेन में पॉइन्ट ब्लेन्क रेंज से गोली मारकर हत्या करने के केस में विदेश फरार हो गये और मुख्य सूत्रधार आरोपी छबील पटेल गुरुवार को सुबह में नाटकीय तरीके से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर से स्पेशियल इन्वेस्टीगेशन टीम (सीट) द्वारा गिरफ्तार की गई थी। हालांकि, छबील पटेल की गंभीर अपराध में शामिल होने के बावजूद भी और यह विदेश फरार हो गया फिर भी ६६ दिन बाद इस तरीके से अचानक पुलिस के समक्ष सामने से आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया इसे लेकर कई सवाल उठाये जा रहे है। पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए गुजरात में मुख्यमंत्री के दावेदार केन्द्र नेता ने पूरा ऑपरेशन किए जाने की चर्चा हो रही है। भाजपा के पूर्व विधायक जयंती भानूशाली की चल रही ट्रेन में गोली मारकर हत्या की गई थी। हत्या की साजिश रचने का आरोप अबडासा के पूर्व विधायक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धी छबील पटेल और मनीषा गोस्वामी पर लगा था। हत्या बाद छबील पटेल फरार था। आरोपी छबील पटेल गुरुवार को सुबह में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर न्यूयॉर्क की अमीरात की फ्लाइट्स में आया तुरंत ही इसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। प्राथमिक पूछताछ में छबील पटेल ने अपराध को स्वीकार कर लिया था। जिसमें भानूशाली के साथ राजनीतिक दुश्मनी और दुश्मनी की वजह से उनकी हत्या की गई यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया था। जयंती भानूशाली की हत्या बाद विदेश फरार हुए छबील पटेल इसके रिश्तेदारों और मित्रों के संपर्क में होने की पुलिस को जानकारी दी थी। इसी वजह से इसका पुत्र सिद्धार्थ पटेल की खोजबीन चल रही थी। गोवा के गेस्ट हाउस में छिपकर रहता था यह सिद्धार्थ भी सामने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। छबील पटेल रिश्तेदारों की गिरफ्तारी तथा इसकी संपत्तियों को जब्त कर लेने की पुलिस की कार्रवाई से छबील कभी भी पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की संभावना व्यक्त की गई थी।

भानूशाली हत्या केस घटनाक्रम

अहमदाबाद।

- **७ जनवरी : सयाजीनगरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे जयंती भानूशाली की १२.५५ करीब गोली मारकर हत्या**
- **८ जनवरी : भानूशाली का भतीजा सुनील ने छबील पटेल सहित ५ शख्सों के विरूद्ध पुलिस शिकायत दर्ज कराई- ७ आईपीएस अधिकारी, ६ डीवायएसपी, ८ पीआई सहित २०० का स्टाफ की एसआईटी बनाई गई**
- **९ जनवरी : अहमदाबाद में भानूशाली की अंतिम संस्कार हुआ, नलिया में लोगों ने बंद रखा, सयाजीनगरी के एच-१ कोच को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सुरक्षित जगह पर रखकर १६ जवान राउन्ड द क्लॉक सिक्यॉरिटी उतारा गया हत्या के ३६ घंटे बाद पुलिस ने एच-१ कोच में घटना का रिकन्स्ट्रक्शन किया**
- **११ जनवरी : रेलवे पुलिस सहित एसआईटी ने सामखियाली पैदल चलकर घटनास्थल पर जांच की, छबील का एक ऑडियो वायरल करके कहा विदेश की बिजनेस मीटिंग पूरा करके गुजरात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा**
- **जयंती भानूशाली की हत्या में सीट की संदिग्धों को साथ में रखकर एच-१ कोच में जांच**
- **२२ जनवरी जयंती भानूशाली हत्या की जांच धीमी होने के आरोप के साथ समाज रास्ते पर आ गया, कांग्रेस के विधायक भी शामिल हुए**
- **२५ जनवरी : सीआईडी क्राइम ने आर्थिक कारणों की वजह से जयंती भानूशाली की हत्या हुई होने का बताकर मनीषा गोस्वामी और भानूशाली का नाम लिया पूर्व विधायक छबील पटेल को भाजपा पार्टी से सस्पेन्ड कर दिया गया**
- **१३ फरवरी : रेलवे पुलिस ने छबील पटेल को भगोड़ा घोषित करने की धारा ७० के अनुसार भचाऊ कोर्ट में करने पर कोर्ट ने अर्जी को मान्य रखकर पुलिस ने इसे भगोड़ा घोषित किया**
- **१७ फरवरी : सापूतारा से भानूशाली हत्या केस में दो संदिग्ध विशाल कांबले और शशीकांत गिरफ्तार**
- **२८ फरवरी : पूना के विशाल कांबले से सीट को कई जानकारी दी जिसमें मनीषा गोस्वामी, सुरजीत परदेशी उर्फ भाउ और निखिल थोराट सहित के शख्सों का नाम सामने आया**
- **छबील पटेल और विशाल कांबले एक-दूसरे को नहीं पहचानते थे लेकिन मनीषा गोस्वामी, सुरजीत ने पहचान कराई**
- **विशाल ने शशीकांत और अनवर को बुलाकर सुपारी दिए जाने का सामने आया**
- **४ मार्च : सीट ने छबील के साथ लगातार संपर्क में रहते स्थानीय मीडिया कर्मचारी मीठू चौहाण को आशंका के आधार पर उठाया गया**
- **७ मार्च : छबील ने गवाह तक पहुंचने के लिए मीठू चौहाण के साथ अपने दो रिश्तेदार ऐसे रसिक पटेल और भतीजा पीयूष वासणी ने पवन मौर्य के घर की रेकी काम सौंपा, पीयूष के मित्र कामेश ने पवन के घर की रेकी की इसकी विडियो बनाकर छबील पटेल को भेजा, सभी आरोपियों के विरूद्ध भूज के बी डीविजन पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया**
- **९ मार्च : सिद्धार्थ पटेल सीट के समक्ष पेश हुए**
- **१० मार्च : छबील पटेल के पुत्र सिद्धार्थ पटेल की १७ घंटे पूछताछ बाद गिरफ्तारी**
- **११ मार्च : पांच आरोपी राहुल पटेल, नीतिन पटेल, शशीकांत कांबले, अशरफ शेख और विशाल कांबले की गिरफ्तारी, विशाल कांबले के रिमांड पूरा होने पर पूना की यरवडा जेल में भेजा गया**
- **१३ मार्च : विदेश से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण होने की बात सामने आई**
- **१४ मार्च : सुबह में अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दुबई से फ्लाइट में आने पर हिरासत में लिया गया**

सूरत। जलाराम नगर महादेव नगर पुंचमुखी हनुमान मंदिर के पास में पानी की लाईन में पिछले दो दिन से लिकेज होने से लाखो लीटर पीने का पानी गट्टर में बह जाने के बाद में वाटर विभाग द्वारा जब इस पाईप लाइन को मरम्मत करने के लिए अपने कर्मचारी भेजे तो उनसे सर्टिट लाइट का वायर कट गया जिसकों रिपेयर करने के लिए सूरत महानगर पालिका के कान्ट्रेक्टर बच्चों के पास से काम करते हुए नजर आए ।

गुजरात में स्वाइन फ्लू से और १ मौत : डर बरकरार

अहमदाबाद । गुजरात में किलर बने स्वाइन फ्लू का आतंक जारी रहा है। स्वाइन फ्लू को काबू में लेने के सभी प्रयास होने के बावजूद भी हररोज स्वाइन फ्लू के नए केस दर्ज किए जा रहे है। गुरुवार को भी स्वाइन फ्लू के कई मामले सामने आये। स्वाइन फ्लू की वजह से गुरुवार को अहमदाबाद में एक की मौत हुई थी स्वाइन फ्लू को लेकर आधिकारिक रूप से एक की मौत की रिपोर्ट आयी है। दूसरी तरफ अहमदाबाद में स्वाइन फ्लू से प्रभावी लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। यहां १२०० से भी ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। मौत का आंकड़ा भी २० से ऊपर पहुंच चुका है। राज्य में एक ही दिन में स्वाइन फ्लू के ५२ नए मरीज सामने आए हैं। एक की मौत भी हो गई। नए मरिजों में सबसे अधिक १२ सूरत मनपा और ११ अहमदाबाद मनपा क्षेत्र में है। गुजरात में पिछले छह माह से स्वाइन फ्लू का प्रकोप है।

राहुल गांधी गुजरात में दस जनसभा संबोधित करेंगे

कांग्रेस में अब उम्मीदवार पसंदगी की कवायद तेज

राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी, सोनिया सहित के स्टाफ प्रचारकों को भी चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा

अहमदाबाद । लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ ही दिन बाकी है तब कांग्रेस में गुजरात की २६ सीटों के लिए उम्मीदवारों की पसंदगी में तेजी लाई गई है। निरीक्षकों की पैनल सहित विभिन्न समितियों द्वारा इस बारे में कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। दूसरी तरफ, लोकसभा चुनाव पहले राहुल गांधी गुजरात में दस जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात कांग्रेस द्वारा चुनाव प्रचार की प्रक्रिया भी आयोजनबद्ध तरीके से शुरू की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के चुनाव प्रचार के तहत दस जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड-शो भी करेंगे। गुजरात के चारों जोन में राहुल गांधी की दो-दो जनसभा आयोजित की जाएगी। राहुल के अलावा प्रियंका, सोनिया गांधी सहित के स्टाफ प्रचारकों को भी चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा।

इस दौरान गुरुवार को पास के युवा नेता और हाल में कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति में कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य पद के लिए पांच रुपये का फॉर्म भरकर पार्टी में विधिवत तरीके से एंट्री किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चावडा ने इस मामले में हार्दिक पटेल को पार्टी में स्वागत किया गया और बताया गया कि, हार्दिक पटेल किसी भी शर्त बिना कांग्रेस में शामिल हुए हैं और सदस्य के तौर पर काम करने के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका महत्व की होगी। कांग्रेस द्वारा हार्दिक पटेल को कहां से लोकसभा टिकट दिया जाता है और चुनाव जंग में किसके विरूद्ध उतारा जाता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। गुजरात कांग्रेस द्वारा राज्य की २६ लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की पसंदगी के लिए महत्व की कवायद शुरू की गई है, जिसमें शहरी क्षेत्र के साथ -साथ ग्रामीण क्षेत्र की सीटों को लेकर मतदाताओं का मूड, उम्मीदवारों की लोकप्रियता, इनके जीतने की संभावना सहित के पहलुओं को ध्यान में लेकर हरएक सीट तीन-तीन उम्मीदवारों के नाम की पैनल तैयार हो रही है।

अहमदाबाद पूर्व से परेश रावल के बदले मनोज जोषी चुनाव लड़ेंगे

अहमदाबाद । २०१४ के लोकसभा चुनाव में गुजरात से सभी २६ सीटें भाजपा को मिली थी तब २०१९ के चुनाव में भी २६ सीटें हासिल करने के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पसंदगी की प्रक्रिया शुरू की है तब अहमदाबाद के पूर्व वर्तमान सांसद और फिल्म कलाकार परेश रावल ने फिर से चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छा बताने पर उनके स्थान पर भाजपा के करीबी माने जाते और पद्मश्री विजेता मनोज जोषी को टिकट दिया जाए ऐसी संभावना रही है। यदि ऐसा हुआ तो मनोज जोषी भाजपा के लिए परेश रावल से ज्यादा मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे इतना ही नहीं, परेश रावल द्वारा अपने क्षेत्र में पर्याप्त समय नहीं देते होने की और स्थानीय प्रश्नों के काम नहीं किए जाने की लोगों ने शिकायत की और इसे दूर किया जा सकता है ऐसा है। मनोज जोषी गुजराती कलाकार होने के बावजूद जनता की समस्या अच्छी तरीके से जानते हैं, इसी वजह से भाजपा की यह पसंदगी साबित होने की संभावना है। २०१४ की लोकसभा में अहमदाबाद पूर्व की सीट से विजेता बने सांसद परेश रावल मत क्षेत्र के कार्यों में विफल रहे।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)